

वदिश मंत्रालय की विकास सहायता

प्रलमिस के लयि:

[अंतरमि बजट 2024-25](#), भारत की 'नेबरहुड फर्सट' नीति, मंगदेछू जलवदियुत परयोजना, [खोलोंगछू HEP](#), [बौद्ध धरम](#)

मेन्स के लयि:

भारत-भूटान संबंघ, भारत और पड़ोसी देश- संबंघ, द्वपिक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्वकि समूह एवं भारत से जुड़े और/या भारत के हतिों को प्रभावति करने वाले समझौते

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में [वतितीय वर्ष 2024-25 के लयि अंतरमि बजट](#) प्रसतुत कयि गया जसिमें [वदिश मंत्रालय \(MEA\)](#) ने रणनीतिक भागीदारों तथा पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रति करते हुए अपनी विकास सहायता योजनाओं की रूपरेखा तैयार की।

- वदिश मंत्रालय की विकास सहायता वदिश नीति के लक्ष्यों के अनुरूप [भारत के वैश्वकि प्रभाव तथा हतिों के वसितार एवं सुरक्षा](#) पर केंद्रति है। इसका उद्देश्य [रणनीतिक विकास सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टविटी, सहयोग एवं स्थरिता](#) को बढ़ावा देना है।

देशों के बीच विकास सहायता का आवंटन कसि प्रकार कयि गया?

- मंत्रालय ने अंतरमि बजट में वतितीय वर्ष 2024-25 के लयि कुल 22,154 करोड़ रुपए आवंटति कयि जबकि वित्त वर्ष का परवियय 18,050 करोड़ रुपए था।
 - [भारत की 'नेबरहुड फर्सट' नीति](#) के अनुरूप [भूटान को विकास सहायता का सबसे बड़ा अंश 2,400 करोड़ रुपए आवंटति कयि गया](#)। वर्ष 2023-24 में भूटान को आवंटति राशा 2,068 करोड़ रुपए थी।
 - [भूटान विकास सहायता का एक बड़ा अंश प्राप्त करते हुए अन्य देशों की सूची में अग्रणी बनकर उभरा है](#)।
 - बजट दस्तावेजों के अनुसार [मालदीव को 770 करोड़ रुपए की विकास सहायता आवंटति की गई](#) जो वगित वर्ष 600 करोड़ रुपए थी।
 - [अफगानसितान](#) के नवासियों के साथ भारत के विशेष संबंधों को जारी रखते हुए देश के लयि [200 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता](#) प्रदान की गई।
 - [बांग्लादेश](#) को विकास सहायता के तहत [120 करोड़ रुपए](#) की राशा प्रदान की जाएगी जबकि [नेपाल](#) को [700 करोड़ रुपए](#) प्रदान कयि जाएंगे।
 - [शरीलंका](#), [मॉरीशस](#) तथा [म्यांमार](#) को क्रमशः [75 करोड़](#), [370 करोड़](#) एवं [250 करोड़ रुपए](#) की विकास सहायता प्रदान की जाएगी।
 - [अफ्रीकी देशों के लयि 200 करोड़ रुपए राशा](#) का आवंटन कयि गया।
 - वभिन्न देशों और क्षेत्रों जैसे [लैटनि अमेरिका](#) तथा [यूरेशया](#) को कुल 4,883 करोड़ रुपए विकास सहायता प्रदान की जाएगी।
 - ईरान के साथ कनेक्टविटी परयोजनाओं पर भारत के फोकस को रेखांकति करते हुए [चाबहार बंदरगाह](#) के विकास के लयि [100 करोड़ रुपए](#) की राशा आवंटति की गई।

वदिश मंत्रालय की अन्य विकास साझेदारियाँ क्या हैं?

- मानवीय सहायता:**
 - वदिश मंत्रालय [प्राकृतिक आपदाओं](#), आपात स्थतियों तथा [महामारी](#) के समय में [भागीदार देशों को मानवीय सहायता](#) प्रदान करता है।
 - भारत ने कई देशों को राहत सामग्री, चकितिसा दल और वतितीय सहायता प्रदान की है तथा [कोवडि-19 महामारी](#) से नपिटने के लयि 150 से अधिक देशों को दवाएँ, टीके एवं चकितिसा उपकरण भी प्रदान कयि हैं।
- सांस्कृतिक और वरिसत सहयोग:**

- वदिश मंत्रालय साझेदार देशों के साथ सांस्कृतिक और वरिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत के सहायता कार्यक्रम से 50 से अधिक सांस्कृतिक तथा वरिष्ठ परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जसमें आनंद मंदिर, श्वेदागोन पैगोडा (म्यांमार), सेक्रेड टूथ रेलिक टेम्पल, कैंडी (श्रीलंका) में भारतीय गैलरी, बालातरिपुरासुंदरी मंदिर का नवीनीकरण, धर्मशाला-पशुपतनाथ मंदिर (नेपाल) का नरिमाण शामिल है।
- वर्तमान में वभिन्न देशों में लगभग 25 सांस्कृतिक और वरिष्ठ परियोजनाएँ कार्यान्वयन की जा रही हैं।
- क्षमता नरिमाण और तकनीकी सहायता:
 - भारत की विकास साझेदारी क्षमता नरिमाण, नागरिक और सैन्य प्रशिक्षण, ऑन-साइट कार्यक्रम तथा मतिर देशों में विशेषज्ञ प्रतनियुक्त की पेशकश को प्राथमिकता देती है।
 - भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम वर्ष 1964 में शुरू किया गया था यह 160 भागीदार देशों तक फैला हुआ है, जो वभिन्न वर्षों में अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, जसमें वर्ष 2019-20 तक 4,000 से 14,000 स्थान (Slot) तक महत्त्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
 - पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं, जो विश्व स्तर पर समग्र कौशल वृद्धि में योगदान करते हैं।
- विकास परियोजनाओं के लिये ऋण शृंखलाएँ:
 - भारत द्वारा भारतीय एकजमि बैंक के माध्यम से भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS) के तहत रियायती ऋण शृंखला (Lines of Credit- LOC) के रूप में विकास सहायता (Development Assistance) प्रदान की जाती है।
 - कुल मिलाकर 30.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 306 LOC 65 देशों तक वसितारति की गई हैं। LOC के तहत परियोजनाएँ परविहन, वदियुत उत्पादन जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों को कवर करती हैं; कृषि, वनरिमाण उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और क्षमता नरिमाण।

भारत के लिये भूटान क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- जटिल संबंधों वाले दो एशियाई दगिगज भारत और चीन के बीच भूटान एक बफर राज्य के रूप में कार्य करता है। भूटान की रणनीतिक स्थिति भारत को उत्तर से संभावित खतरों के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है।
- वर्ष 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरिध के दौरान, भूटान ने चीनी घुसपैठ का वरिध करने के लिये भारतीय सैनिकों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये भारत का पूरण समर्थन सीमा पार कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और व्यापार, बुनियादी ढाँचे तथा ऊर्जा में संबंधों का वसितार करने की प्राथमिकताओं पर आधारित है।
- भारत सरकार ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2018-2023) के लिये 45 अरब रुपए देने की प्रतबिद्धता जताई है, जसमें प्रोजेक्ट टाईड अससिटेस (PTA) हेतु 28 अरब रुपए शामिल हैं।
 - PTA कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पशुधन विकास और बुनियादी ढाँचे सहित वभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएँ शामिल हैं।
- भूटान में सतही विकास के लिये भारत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (High Impact Community Development Projects -HICDPs)/लघु विकास परियोजनाओं (Small Development Projects - SDPs) के लिये प्रतबिद्ध है।
 - ये खेतों तक सड़क पहुँच, पशुधन केंद्र, जल आपूर्ति और सचिाई प्रणाली तथा स्थानीय स्तर पर क्षमता विकास जैसे अवसंरचनात्मक नरिमाण के लिये भूटान के दूरदराज के हसिसों में स्थिति छोटी अवधि की लघु परियोजनाएँ हैं।
- भूटान के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद जल-वदियुत सहयोग द्वपिक्षीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है। भूटान के लिये, जल-वदियुत विकास सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक बना हुआ है।
- जलवदियुत क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच चल रहा सहयोग वर्ष 2006 के द्वपिक्षीय सहयोग समझौते और वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित इसके प्रोटोकॉल के तहत शामिल है।
 - भूटान में कुल 2136 मेगावाट की चार जलवदियुत परियोजनाएँ (hydroelectric projects- HEPs) पहले से ही चालू हैं और भारत को बजिली की आपूर्ति कर रही हैं।
 - 720 मेगावाट की मंगदेछु (Mangdechhu) जलवदियुत परियोजना को अगस्त 2019 में चालू किया गया था और दसिंबर 2022 में भूटान को सौंप दिया गया था।
 - दोनों देश 1200 मेगावाट की पुनात्सांगछु-I (Punatsangchhu-I) एवं 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछु-II (Punatsangchhu-II) सहित अन्य परियोजनाओं का कार्यान्वयन वभिन्न चरणों में हैं।
 - दोनों देशों ने पहली बार संयुक्त उद्यम परियोजना 600 मेगावाट खोलेंगछु जलवदियुत परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य भूटान के लिये अधिशेष जलवदियुत पैदा करना है जसिे भारत को नरियात किया जाएगा, जसिसे भूटान के राजस्व के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।
- भारत आयात स्रोत और नरियात गंतव्य दोनों के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार है।
- दोनों पड़ोसियों के बीच सदियों पुराना घनषिठ सम्भ्यतागत, सांस्कृतिक संबंध है। भूटानभारत को ग्यागर अर्थात पवतिर भूमिमानता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी, जो कबिहुसंख्यक भूटानी लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला धर्म है।

भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति (India's Neighbourhood First Policy):

- भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' अपने नकिटतम पड़ोस के देशों, यानी अफगानसितान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकसितान और श्रीलंका के साथ संबंधों के प्रबंधन के प्रतबिद्ध इसके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती है।
- नेबरहुड फर्स्ट नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में भौतिक, डिजिटल और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार तथा वाणज्य को बढ़ाना है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????:

प्रश्न: शीत युद्ध के बाद के अंतरराष्ट्रीय परदृश्य के संदर्भ में भारत की लुक ईस्ट नीति (पूरव की ओर देखो नीति) के आर्थिक और रणनीतिक आयामों का मूल्यांकन कीजिये। (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mea-s-development-aid>

